



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 माघ 1938 (श10)

(सं0 पटना 119) पटना, वृहस्पतिवार, 16 फरवरी 2017

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचनाएं

15 फरवरी 2017

बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं फुटपाथ विक्रय विनियमन) स्कीम, 2017

सं0 04/SV(NULM)-04/2015-415/न0वि0एवंआ0वि0—बिहार फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं फुटपाथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (केन्द्रीय अधिनियम 7/2014) की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार नगर स्थानीय निकायों एवं शहरी फुटपाथ विक्रय समितियों से परामर्श कर एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित स्कीम बनाती है, यथा—

अध्याय—I

प्रस्तावना।

- संक्षिप्त नाम एवं आरंभ।**— (1) यह स्कीम बिहार राज्य फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं फुटपाथ विक्रय विनियमन) स्कीम, 2017 कही जा सकेगी।  
(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें तथा राज्य की विभिन्न नगरपालिकाओं के लिए अलग-अलग तारीख नियत की जा सकेगी।
- परिभाषाएँ।**— (1) इस स्कीम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो —
  - 'अधिनियम' से अभिप्रेत है फुटपाथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं फुटपाथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 केन्द्रीय अधिनियम 7/2014;
  - 'उपयुक्त सरकार' से अभिप्रेत है बिहार सरकार;
  - 'स्थानीय प्राधिकार' से अभिप्रेत है नगर निगम या नगर परिषद् या नगर पंचायत या जिस नाम से जाना जाता हो (या छावनी बोर्ड, या जैसी स्थिति हो, छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 47 के अधीन नियुक्त असैनिक क्षेत्र समिति या ऐसा कोई अन्य निकाय, जो उस नगर या शहर में नागरिक सेवाएँ उपलब्ध कराने एवं फुटपाथ विक्रय विनियमित करने हेतु किसी नगर या शहर में स्थानीय प्राधिकार के रूप में कृत्य करने को अधिकृत हो;
  - 'अधिसूचना' से अभिप्रेत है राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना और पद 'अधिसूचित करना' तदनुसार समझा जाएगा;
  - 'फुटपाथ विक्रेताओं से अभिप्रेत है, ऐसे व्यक्ति, जो दिनानुदिन उपयोगी वस्तुओं, उत्पादों, खाद्य सामग्रियों और सदृश पदार्थों को गली, फुटपाथ, सड़क, खड़जा, पार्श्वपथ, सार्वजनिक पार्क या

किसी अन्य सार्वजनिक स्थान अथवा निजी क्षेत्र या किसी अस्थायी संरचना पर फुटपाथ विक्रय में लगे रहते हैं या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते हुए विक्रय करते हैं, और इस फुटपाथ विक्रय में पैसे पर आधारित सेवा उपलब्ध कराना भी शामिल है और ऐसे फुटपाथ विक्रेताओं के नाम स्थानीय या क्षेत्र विशेष के आधार पर फेरीवाला, ठेलावाला, खोमचावाला, रेहड़ीवाला जैसे पर्यायवाची नाम शामिल हो सकते हैं और अपने व्याकरणात्मक फेर-फार और सजातीय अभिव्यक्तियों सहित 'फुटपाथ विक्रय' शब्द तदनुसार सन्निर्मित किया जाएगा;

- (च) 'स्थायी फुटपाथ विक्रेताओं' से अभिप्रेत है ऐसे फुटपाथ विक्रेता, जो किसी स्थान विशेष पर रोजाना फुटपाथ विक्रय में लगे रहते हैं;
- (छ) 'चलंत फुटपाथ विक्रेता' से अभिप्रेत है ऐसे फुटपाथ विक्रेता, जो अपने उत्पादों को विक्रय करने एवं पैसे पर आधारित सेवाएँ देने के लिए अभिहित क्षेत्र में विक्रय क्रिया-कलाप एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए करते हो;
- (ज) 'त्योहारी बाजार' से अभिप्रेत है ऐसा बाजार, जहाँ नगर या शहर के त्योहार के दिनों में विक्रेता एवं क्रेता उत्पादों के विक्रय एवं क्रय के लिए या पैसे पर आधारित सेवाओं के लिए परंपरागत रूप से एकत्रित होते हैं और जो शहरी फुटपाथ विक्रय समिति की अनुशंसाओं पर, स्थानीय प्राधिकार द्वारा इस रूप में अवधारित किए गए हों;
- (झ) 'विरासती बाजार' से अभिप्रेत है ऐसा बाजार, जो एक ही स्थान पर 50 वर्षों से अधिक समय तक अस्तित्व में रहा हो और जहाँ विक्रेता एवं क्रेता उत्पादों के विक्रय एवं क्रय के लिए तथा पैसे पर आधारित सेवाओं के लिए परंपरागत रूप से एकत्रित होते रहे हैं और जो शहरी फुटपाथ विक्रय समिति की अनुशंसाओं पर स्थानीय प्राधिकार द्वारा इस रूप में अवधारित किए गए हों;
- (ञ) 'प्राकृतिक बाजार' से अभिप्रेत है ऐसा बाजार, जहाँ विक्रेता एवं क्रेता उत्पादों के विक्रय एवं क्रय के लिए तथा पैसे पर आधारित सेवाओं के लिए परंपरागत रूप से एकत्रित होते रहे हैं और जो शहरी फुटपाथ विक्रय समिति की अनुशंसाओं पर स्थानीय प्राधिकार द्वारा इस रूप में अवधारित किए गए हों;
- (ट) 'ताख बाजार' से अभिप्रेत है ऐसा बाजार जहाँ विक्रेता एवं क्रेता ताख पर रखने योग्य उत्पादों के विक्रय एवं क्रय के लिए तथा पैसे पर आधारित सेवाओं के लिए परंपरागत रूप से एकत्रित होते रहे हैं और जो शहरी फुटपाथ विक्रय समिति की अनुशंसाओं पर स्थानीय प्राधिकार द्वारा इस रूप में अवधारित किए गए हों;
- (ठ) 'रात्रि बाजार' से अभिप्रेत है ऐसा बाजार, जहाँ विक्रेता एवं क्रेता उत्पादों के विक्रय एवं क्रय के लिए पैसे पर आधारित सेवाओं के लिए परंपरागत रूप से शाम के बाद यानी रात्रि के समय एकत्रित होते रहे हैं और जो शहरी फुटपाथ विक्रय समिति की अनुशंसाओं पर स्थानीय प्राधिकार द्वारा इस रूप में अवधारित किए गए हों;
- (ड) 'मौसमी बाजार' से अभिप्रेत है ऐसा बाजार, जहाँ किसी विशेष मौसम के दरम्यान विक्रेता एवं क्रेता उत्पादों के विक्रय एवं क्रय के लिए तथा पैसे पर आधारित सेवाओं के लिए परंपरागत रूप से एकत्रित होते रहे हैं और ऐसे बाजार शहरी फुटपाथ विक्रय समिति की अनुशंसाओं पर स्थानीय प्राधिकार द्वारा अवधारित किए गए हों;
- (ढ) 'साप्ताहिक बाजार' से अभिप्रेत है ऐसा बाजार, जहाँ सप्ताह में किसी खास दिन विक्रेता एवं क्रेता उत्पादों के विक्रय एवं क्रय के लिए तथा पैसे पर आधारित सेवाओं के लिए परंपरागत रूप से एकत्रित होते रहे हैं और ऐसे बाजार शहरी फुटपाथ विक्रय समिति की अनुशंसाओं पर स्थानीय प्राधिकार द्वारा अवधारित किए गए हों;
- (ण) 'शहरी फुटपाथ विक्रय समिति' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 22 के अधीन उपयुक्त सरकार द्वारा गठित निकाय;
- (त) 'फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र' से अभिप्रेत है फुटपाथ विक्रय के लिए फुटपाथ विक्रेताओं द्वारा किए जानेवाले विशेष उपयोग के लिए ऐसा क्षेत्र या स्थान, जो शहरी फुटपाथ विक्रय समिति की अनुशंसाओं पर स्थानीय प्राधिकार द्वारा अभिहित हो और ऐसी जगह या स्थान में फुटपाथ, पार्श्वपथ, खड़्जा, मेड़, सड़क का कोई हिस्सा, सार्वजनिक प्रतीक्षालय या ऐसा कोई स्थान सम्मिलित है, जो फुटपाथ विक्रय और सामान्य जन को पैसे पर आधारित सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त समझा गया हो;
- (थ) 'योजना' से अभिप्रेत है धारा 22 की प्रथम अनुसूची के अधीन बनाई गई योजना;
- (द) 'योजना प्राधिकार' से अभिप्रेत है मास्टर योजना या विकास योजना या प्रक्षेत्रीय योजना या अभिन्यास योजना या किसी अन्य स्थानिक योजना में किसी विशेष क्रिया-कलाप के लिए क्षेत्रों के ठीक ठाक विस्तार को परिभाषित करते हुए भूमि उपयोग के विनियमन हेतु उत्तरदायी उपयुक्त सरकार द्वारा किसी नगर या शहर में अभिहित नगर विकास प्राधिकार या कोई अन्य प्राधिकार जो, यथास्थिति, तत्समयप्रवृत्त शहर और देहात योजना अधिनियम या नगर विकास अधिनियम या नगरपालिक अधिनियम के अधीन वैधतः लागू होने योग्य।

- (घ) 'सार्वजनिक उद्देश्य' में अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित सम्मिलित है—
- (क) मार्गों, सड़कों, गलियों को चौड़ा करना;
- (ख) मार्गों, सड़कों, गलियों के पथ-पृष्ठों का स्थान बदलना;
- (ग) भूमिगत मार्ग बनाना;
- (घ) कुछ सार्वजनिक परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक प्राधिकारों के स्वामित्व वाली भूमि का विकास;
- (ङ.) जल एवं नाली की व्यवस्था करना;
- (च) सेवाओं के लिए मध्यवर्ती पम्पिंग स्टेशन स्थापित करना;
- (छ) बिहार पथ परिवहन सेवा, मेट्रो आदि जैसे, सार्वजनिक यातायात से संबंधित कोई परियोजना;
- (ज) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवासन की व्यवस्था;
- (झ) उद्यान, वाटिका और मनोरंजक क्षेत्र बनाया जाना;
- (ञ) उस क्षेत्र में पारिस्थितिक संसाधन का संरक्षण और
- (ट) स्थानीय प्राधिकार द्वारा लिया गया कोई अन्य विकास कार्य, जिसके हिताधिकारी बड़े पैमाने पर समुदाय होगा;
- (न) 'स्कीम' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 38 की द्वितीय अनुसूची के अधीन बनाया गया स्कीम;
- (प) 'धारा' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा;
- (फ) 'धारण क्षमता' से अभिप्रेत है फुटपाथ विक्रेताओं की अधिकतम संख्या, जिसे किसी फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र में समायोजित किया जा सकता है और जिसे शहरी फुटपाथ विक्रय समिति की अनुशंसाओं पर स्थानीय प्राधिकार द्वारा अवधारित किया गया हो;
- (ब) 'शिकायत निवारण समिति' से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन बिहार सरकार द्वारा गठित समिति;

2. अधिनियम में परिभाषित और इस स्कीम में प्रयुक्त किंतु अपरिभाषित शब्द और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में कमशः उनके प्रति समानुदेशित किए गए हों।

## अध्याय—II सर्वेक्षण की रीति।

3. **सर्वेक्षण की प्रक्रिया।**—(1) नगर विक्रय समिति स्वयं या अन्य उपयुक्त एजेंसी द्वारा सर्वेक्षण करायेगा।
- (2) प्रस्ताव का पर्याप्त प्रचार निम्नलिखित रीति से की जायेगी :—
- (i) अपना वेवसाईट पर,
- (ii) क्षेत्र के स्थानीय भाषा में कोई दो प्रसिद्ध स्थानीय समाचार-पत्र में प्रकाशन द्वारा,
- (iii) कार्यालय के सूचनापट्ट पर लगाना, और
- (iv) स्थानीय प्राधिकरण के क्षेत्रांतर्गत स्थानीय बाजार के किसी विशिष्ट स्थान पर एक प्रति लगाना।
- (3) पूर्व सूचना के पश्चात् फुटपाथ विक्रेता के सर्वेक्षण के लिये कैम्प का आयोजन किया जा सकता है।
4. सर्वेक्षण का प्रतिफल डिजिटल प्रपत्र में उपलब्ध कराया जायेगा।
5. सर्वेक्षण प्रतिवेदन में इस बात का भी विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि फुटपाथ विक्रय करने का माध्यम कौन-सा है और इसको मानचित्र पर दर्शाया भी जाएगा। फुटपाथ विक्रय की रीति निम्नलिखित में से कोई भी हो सकती है:—
- (1) टेलागाड़ी/मोटरवाहन;
- (2) जमीन पर रखकर-बिछाकर;
- (3) खोमचा तथा लकड़ा का इस्तेमाल कर
6. अधिनियम के उपबंधों और स्कीम में अंतर्विष्ट उपबंधों के अध्यक्षीन, शहरी फुटपाथ विक्रय समिति, यथासाध्य सुनिश्चित करेगी कि कंडिका (3) के अधीन किए गए सर्वेक्षण में चिह्नित सभी विद्यमान फुटपाथ विक्रेता फुटपाथ विक्रय क्षेत्र में समायोजित हों।

### अध्याय-III

#### पहचान पत्र एवं विक्रय प्रमाण पत्र निर्गत करने की रीति ।

7. वह अवधि, जिसके अंतर्गत सर्वेक्षणाधीन चिह्नित फुटपाथ विक्रेताओं को पहचान पत्र एवं फुटपाथ विक्रय का प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाएगा- सर्वेक्षण के दौरान चिह्नित फुटपाथ विक्रेताओं को सर्वेक्षण की तिथि से छः महीने की अधिकतम समयावधि के भीतर पहचान पत्र एवं प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाएगा।

8. शर्तें एवं निबंधन, जिसके अध्यक्षीन फुटपाथ विक्रेता को और ऐसे व्यक्तियों को भी जो दो सर्वेक्षणों के बीच में पड़ने वाले अवधि में फुटपाथ विक्रय करने की इच्छा रखते हों, को पहचान पत्र एवं प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा सकेगा। मानदंड जिसके तहत फुटपाथ विक्रेताओं को, पहचान पत्र एवं विक्रय प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाएगा-

- (i) शहरी फुटपाथ विक्रय समिति द्वारा किए गए सर्वेक्षण में नाम होगा ;
- (ii) केवल फुटपाथ विक्रय में ही लगा होगा, न कि किसी अन्य पेशे में ;
- (iii) उसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य स्थान में कोई और दूसरा फुटपाथ विक्रय का स्थल न हो, फिर भी उसके जीवन सहचर और चौदह वर्ष की आयु से ऊपर के बच्चे को अलग फुटपाथ विक्रय स्थल हो सकता है;
- (iv) स्वयं द्वारा या परिवार या किसी अन्य व्यक्ति (जिसकी आयु चौदह वर्ष हो चुकी हो) द्वारा फुटपाथ विक्रय किया जा सकेगा;
- (v) कोई भी फुटपाथ विक्रेता जिसने चौदह वर्ष की आयु पूरी कर ली हो;
- (vi) नये फुटपाथ विक्रेता जो दो सर्वे की अवधि के बीच, फुटपाथ विक्रय करना चाहते हैं, वे नगर विक्रय समिति के समक्ष पहचान पत्र एवं विक्रय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कर सकेंगे।

9. प्रपत्र और रीति, जिस प्रारूप और जिस रीति से फुटपाथ विक्रय प्रमाण-पत्र फुटपाथ विक्रेता को निर्गत किया जाएगा-

- (i) फुटपाथ विक्रेता का फोटो-
- (ii) फुटपाथ विक्रेता का नाम-
- (iii) फुटपाथ विक्रेता के साथ लगे हुए उसके आश्रित सहभागी या आश्रित बच्चे का नाम-
- (iv) व्यक्ति/ व्यक्तियों की आयु एवं लिंग, जिनके फोटो दिए गए हों-
- (v) आवास का पता-
- (vi) फुटपाथ विक्रेता की कोटि (चलंत/स्थायी/प्राकृतिक/साप्ताहिक आदि)-
- (vii) फुटपाथ विक्रय का स्थल (क्या यह ऐतिहासिक स्थान या पार्क या बाजार या विद्यालय/महाविद्यालय/ अस्पताल/ बस-पड़ाव या मॉल आदि के सामने है।)-
- (viii) नगरपालिक निकाय का नाम-
- (ix) फुटपाथ विक्रय प्रमाण-पत्र निर्गत करने की तिथि-
- (x) विधि मान्यता (चूंकि कानून प्रत्येक पाँच वर्ष पर सर्वेक्षण का उपबंध करता है, फुटपाथ विक्रय प्रमाण-पत्र भी पाँच वर्ष के लिए निर्गत होना चाहिए-
- (xi) अनन्य रजिस्ट्रेशन संख्या-

10. प्रपत्र और रीति, जिस प्रारूप में तथा जिस रीति से फुटपाथ विक्रेताओं को पहचान-पत्र निर्गत किया जाना है-

- (i) फुटपाथ विक्रेता का नाम-
- (ii) आयु-
- (iii) लिंग-
- (iv) आवास का पता-
- (v) फुटपाथ विक्रय-स्थल का पता-
- (vi) फोटो-
- (vii) दूरभाष संख्या-
- (viii) फुटपाथ विक्रय की कोटि-
- (ix) नगरपालिक वार्ड या प्रक्षेत्र संख्या-
- (x) थाना-
- (xi) विधिमान्यता अवधि-
- (xii) प्राधिकार का हस्ताक्षर मुहर सहित-

11. पहचान पत्र एवं विक्रय प्रमाण-पत्र की विधिमान्यता अवधि- पहचान पत्र एवं विक्रय प्रमाण-पत्र फीस भुगतान की साधारण प्रक्रिया के तहत प्रत्येक पाँच वर्षों की अवधि के पश्चात् नवीकृत की जाएगी। फीस जमा किया जाना और रसीद निर्गत किया जाना, दोनों को, फुटपाथ विक्रय प्रमाण-पत्र के नवीकरण का पर्याप्त साक्ष्य समझा जाएगा।

#### अध्याय-IV

#### विक्रय प्रमाण पत्र का नवीकरण, निलंबन एवं रद्दीकरण।

12. अवधि जिसके लिए और वह रीति जिस रीति से फुटपाथ विक्रय का प्रमाण-पत्र नवीकृत किया जाएगा और ऐसे नवीकरण के लिए फीस।-

- (1) फुटपाथ विक्रय प्रमाण-पत्र प्रत्येक पाँच वर्षों के लिए नवीकृत किया जा सकेगा। फीस जमा किया जाना और फुटपाथ विक्रय प्रमाण-पत्र का नवीकरण की साधारण प्रक्रिया होगी।  
नगर विक्रय समिति ऐसे फुटपाथ विक्रेताओं की सूची प्रदर्शित करेंगी, जिनके फुटपाथ विक्रय प्रमाण-पत्र के नवीकरण की उचित तिथियाँ दो महीनों की अवधि के भीतर हो। उक्त सूची में नवीकरण में लगनेवाली रकम और नवीकरण के स्थान या संस्था भी उपदर्शित हो, ताकि पता चले कि रकम कहाँ जमा करना है और नवीकरण की प्रक्रिया कहाँ होगी।
- (2) नगर विक्रय समिति फुटपाथ विक्रय प्रमाण-पत्र को नवीकरण फीस का भुगतान करने में चूक करने वाले फुटपाथ विक्रेताओं की सूची प्रकाशित करेगी।
- (3) फुटपाथ विक्रय का नवीकरण फीस रुपये 500/- से कम नहीं होनी चाहिए।
- (4) बिना किसी अर्थ-दंड के एक महीने की अवधि की सुविधा उन्हें दी जाएगी।
- (5) पहचान पत्र या विक्रय प्रमाण पत्र खो जाने की स्थिति में, नगर विक्रय समिति फुटपाथ विक्रेता से पचास रू0/ की प्राप्ति के पश्चात्, पहचान पत्र या विक्रय प्रमाण पत्र की अनुलिपि जारी कर सकती है,।

13. रीति जिस रीति से फुटपाथ विक्रय प्रमाण-पत्र निलंबित या रद्द किया जा सकेगा।-शहरी फुटपाथ विक्रय समिति फुटपाथ विक्रय प्रमाण-पत्र में अधिकथित शर्तों के भंग किए जाने के दोषी पाए जाने वाले उत्पाद विक्रेता पर जुर्माना अधिरोपित करेगी और चेतावनी देगी। शर्तों के भंग में निम्नलिखित बातें होंगी:-

- (i) यदि फुटपाथ विक्रेता फुटपाथ विक्रय अनुज्ञप्ति में उल्लिखित क्षेत्र/ बाजार से इतर जगह में फुटपाथ विक्रय कर रहा हो;
- (ii) उसने फुटपाथ विक्रय प्रमाण-पत्र पाने के लिए अपनी आयु की बाबत गलत सूचना दी हो (न्यूनतम आयु 14 वर्ष होनी चाहिए);
- (iii) यदि आवंटित क्षेत्र को बढ़ा लिया जाए या अतिरिक्त क्षेत्र को अनधिकृत रूप से कब्जा में कर लिया गया हो;
- (iv) खाद्य सामग्रियों के फुटपाथ विक्रेताओं की स्थिति में यदि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के अधीन रजिस्ट्रेशन न कराया गया हो;
- (v) यदि आवंटित स्थान पर स्थायी संरचना बना दिया गया है
- (vi) यदि फुटपाथ विक्रय प्रमाण-पत्र को किसी अन्य व्यक्ति को बेचा या पट्टे पर दिया जाए;
- (vii) यदि नवीकरण की विहित अवधि के समापन के पश्चात् फुटपाथ विक्रय प्रमाण-पत्र का नवीकरण न किया गया हो;
- (viii) यदि किसी फुटपाथ विक्रेता ने चौदह वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को इस काम में लगा दिया हो। बाल-श्रम (प्रतिषेध एवं उपविधि विनियमन) अधिनियम 2005 के तहत ऐसे फुटपाथ विक्रेता को शहरी फुटपाथ विक्रय समिति द्वारा चेतावनी दी जाएगी। ऐसे फुटपाथ विक्रेता द्वारा न मानने पर उनका फुटपाथ विक्रय प्रमाण-पत्र रद्द कर दिया जाएगा।
- (ix) महिला फुटपाथ विक्रेता से दुर्व्यवहार करने के दोषी फुटपाथ विक्रेता को एक चेतावनी दी जाएगी, जब व्यथित द्वारा लिखित शिकायत की गई हो।
- (x) शहरी फुटपाथ विक्रय समिति को कार्य-स्थल पर महिलाओं की सुरक्षा हेतु घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 और भारतीय दंड संहिता के अधीन महिला पदधारी की अध्यक्षता वाली एक समिति गठित करनी चाहिए।

### अध्याय-V

#### फुटपाथ विक्रेता की कोटि एवं फीस।

14. फुटपाथ विक्रेताओं की कोटियाँ। - फुटपाथ विक्रेताओं को भी निम्न रूपेण कोटिगत किया जा सकता है:-

- (i) स्थायी ;
- (ii) चलंत ;
- (iii) कोई अन्य, जिसे राज्य सरकार किसी नाम से उपबंधित करे।

15. पहचान पत्र एवं विक्रय प्रमाण - पत्र निर्गत करने हेतु अधिमानता पर आधारित व्यक्तियों की अन्य कोटियाँ। - नगर विक्रय समिति वरीय नागरिक, दिव्यांग, एकाकी माँ और विधवाओं के लिए प्राथमिकता तय करेगी।

16. फुटपाथ विक्रय की कोटि पर आधारित विभिन्न नगरों के लिए अलग-अलग भुगतान की जाने वाली फुटपाथ विक्रय फीस। - फुटपाथ विक्रय फीस फुटपाथ विक्रेताओं की कोटि और बाजार की स्थिति को देखते हुए तय होगी।

(व्याख्या - संभावित आय हर क्षेत्र में अलग-अलग होता है, जहाँ लोग ज्यादा एकत्रित होते हैं, वहाँ फुटपाथ विक्रय अधिक होने की संभावना होती है, सिवाय उसके जहाँ लोग कम संख्या में एकत्रित होते हैं। इसलिए फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्रों की विभिन्न कोटियों के लिए विभिन्न दरों पर फीस नियत करना उचित होगा। विभिन्न कोटियों के नगरों और शहरों के लिए भी अलग-अलग दरें तय की जाएगी।)

शहरी फुटपाथ विक्रय समिति क्षेत्र विशेष में व्यक्तियों के इकट्ठा होने के मद्देनजर फुटपाथ विक्रय से आमद का आकलन करते हुए फीस/उद्ग्रहण तय करेगी, लेकिन यह फीस प्रतिमाह न्यूनतम रुपये 150/- और अधिकतम रुपये 1500/-होगी। प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 10% की वृद्धि फीस में होगी। स्थानीय प्राधिकार फुटपाथ विक्रय फीस वार्षिक रूप से संग्रह कर सकता है, यदि यह उपयुक्त समझा जाए।

17. बैंकों, स्थानीय प्राधिकार के काउंटरों और शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के काउंटरों के माध्यम से फुटपाथ विक्रय शुल्क संग्रहण, रजिस्ट्रेशन के लिए प्रभार और अर्थ-दंड के संधारण, चलंत स्टॉलों के लिए वाहन पड़ाव स्थल के उपयोग और नागरिक सेवाओं की उपलब्धता की बाबत रीति।-प्रत्येक शहरी फुटपाथ विक्रय समिति को एक बैंक खाता होगा और फुटपाथ विक्रेता विहित प्रपत्र में ब्योरा के साथ उस लेखा में प्रतिमाह या प्रतिवर्ष रकम जमा करेंगे। लेखा की वार्षिक संपरीक्षा शहरी फुटपाथ विक्रय समिति द्वारा पूरी की जाएगी। संबंधित स्थानीय प्राधिकार शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के लिए संग्रहण हेतु अपनी कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए स्वतंत्र है।

### अध्याय-VI

#### फुटपाथ विक्रेता के विस्थापन एवं पुनर्स्थापन।

18. सार्वजनिक प्रयोजन, जिसके लिए किसी फुटपाथ विक्रेता को विक्रय का पुनर्स्थापन नियत किया जा सकेगा और पुनर्स्थापन नियत करने की रीति।-

(1) सार्वजनिक प्रयोजन की कोई परियोजना जो परियोजना संबंधित क्षेत्र में फुटपाथ विक्रेताओं के स्थायी या अस्थायी रूप से जगह बदले जाने की अपेक्षा करती हो, वहाँ संबंधित प्राधिकार पुनर्स्थापन अवधारण के लिए निम्नलिखित दो बिन्दुओं पर विचार करेंगे :-

- (i) निर्माण/विकास की समयावधि में फुटपाथ विक्रेताओं को नजदीकी स्थान पर स्थायी रूप से या अस्थायी रूप से समायोजित किया जा सकेगा।
- (ii) परियोजना के पूरा होने के पश्चात् उस सार्वजनिक प्रयोजन के क्षेत्र में फुटपाथ विक्रेताओं को उसी स्थान पर संभव होने की हद तक समायोजित किया जा सकेगा, लेकिन न तो यह अनिवार्य है और न तो अधिदेशात्मक।

(2) किसी सार्वजनिक प्रयोजन के अधीन फुटपाथ विक्रेताओं का पुनर्वास निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखने की अपेक्षा करेगा -

- (क) जहाँ से फुटपाथ विक्रेताओं का स्थान बदला जाना है, उस क्षेत्र में व्यक्तियों के जमावड़ा की स्थिति का आकलन,
- (ख) ऐसे फुटपाथ विक्रेताओं की कुल संख्या, जिनका स्थान बदला जाना हो,
- (ग) वैकल्पिक स्थलों पर जमावड़ा की स्थिति,
- (घ) वैकल्पिक स्थलों पर धारण क्षमता,
- (ङ) परियोजना की समाप्ति के पश्चात् फुटपाथ विक्रय स्थल की संभावित उपलब्धता,
- (च) फुटपाथ विक्रेताओं के जगह बदले जाने की बाबत नए स्थलों का स्थायी आवंटन खेपों में किया जा सकेगा,

- (छ) उस स्थिति में जब मूल स्थल के फुटपाथ विक्रेताओं की संख्या उस संख्या से अधिक हो, जिसे परियोजना की समाप्ति के पश्चात् समायोजित किया जा सकेगा, खेप द्वारा आवंटन अपनाई जा सकती है,
- (ज) सरकारी जमीन पर व्यवसाय करने वाले फुटपाथ विक्रेताओं को या तो सार्वजनिक प्राधिकार के स्वामित्व वाले भूखंड में रखा जा सकता है, या फिर सड़क पर स्थान की उपलब्धता को देखते हुए उन्हें वहाँ विक्रय करने दिया जा सकता है,

**19. फुटपाथ विक्रेता को बेदखल करने की रीति।** – (1) शहरी फुटपाथ विक्रय समिति को अपनी कार्यसूची प्रस्तुत करनी चाहिए और बेदखली के एक माह की नोटिस के निर्गत के पूर्व दो महीने पहले फुटपाथ विक्रेताओं की बेदखली के मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए, ताकि फुटपाथ विक्रेताओं के लिए उसी तरह के फुटपाथ विक्रय स्थल को चिह्नित करने के लिए सर्वेक्षण कराया जा सके।

- (2) बेदखली की प्रक्रिया के पूर्व एक महीने के लिखित नोटिस फुटपाथ विक्रेता के नाम से रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा तामील कराया जाना चाहिए। इसे हाथों – हाथ भी तामील कराया जा सकता है।
- (3) उस स्थिति में, जब रजिस्ट्रीकृत डाक अवितरित हुए लौट जाए, तो उक्त नोटिस को उस क्षेत्र में चिपका देना चाहिए, जहाँ पर वह फुटपाथ विक्रय कर रहा है और इसको भी नोटिस का तामील किया जाना समझा जाए।

**20. फुटपाथ विक्रेता को बेदखली का नोटिस देने की रीति।**— नोटिस देने की रीति निम्नलिखित होगी:—

- (1) अधिनियम की धारा 18 के अधीन बेदखली के एक माह पूर्व नोटिस
- (2) बेदखली का नोटिस फुटपाथ विक्रेता के नाम से होना चाहिए, जिसे रजिस्ट्रीकृत डाक या हाथों—हाथ नोटिस तामिला करते हुए उसके फुटपाथ विक्रय वाली जगह से बेदखल किया जाना है।

**21. बेदखल में चूक करने पर भौतिक रूप से फुटपाथ विक्रेता को बेदखल की रीति:—**

- (1) अधिनियम की धारा 18 के अधीन ऐसे फुटपाथ विक्रेता, जो बेदखली नोटिस अवधि के समापन के बाद जगह नहीं छोड़ते हैं, को उस जगह पर बने रहने के लिए प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान करना पड़ेगा।
- (2) फुटपाथ विक्रेता द्वारा भुगतये व्यतिक्रम रकम या अर्थ—दंड केवल रू0 250/— तक ही हो सकता है। फिर भी, अर्थ – दंड की रकम जब्त मालों के मूल्य से अधिक नहीं होगी।

## अध्याय—VII

### वस्तुओं की जप्ती।

**22. स्थानीय प्राधिकार द्वारा मालों की जप्ती, जप्त वस्तुओं की सूची बनाये जाने और उसे निर्गत करने की रीति।**— अधिनियम की धारा 19 के अधीन वस्तुओं की जप्ती की बाबत निम्नलिखित कदम उठाया जा सकेगा:—

- (i) स्थानीय प्राधिकार के केवल प्राधिकृत व्यक्ति ही वस्तुओं की जप्ती करेंगे;
- (ii) जब्त वस्तुओं की सूची संबद्ध प्राधिकार द्वारा बनाई जाएगी और उसे संबद्ध प्राधिकार द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा;
- (iii) ऐसे फुटपाथ विक्रेता को जिनके सामानों की जप्ती की गई हो प्राधिकार द्वारा सही रसीद दिया जाएगा।

**23. फुटपाथ विक्रेताओं द्वारा अपने जब्त किए गए मालों की पुनर्प्राप्ति की रीति और इसके लिए फीस।**— (1) धारा 19 (2) के अधीन स्थानीय प्राधिकार शीघ्र नष्ट होने वाले जब्त मालों को ऐसी जप्ती के ही दिन विमुक्त कर सकेगा और शीघ्र नष्ट न होने वाले मालों को दो कार्यदिवसों के भीतर विमुक्त कर सकेगा।

- (2) मालों की पुनर्प्राप्ति हेतु फुटपाथ विक्रेता द्वारा भुगतान की जाने वाली फीस उस विक्रेता के कुल जब्त मालों के मूल्य से अधिक नहीं हो सकेगी।
- (3) बिना प्रमाण – पत्र के फुटपाथ विक्रय करने की स्थिति में, ऐसे फुटपाथ विक्रेताओं के जब्त मालों की पुनर्प्राप्ति के लिए प्रभार रू0 500/— से अधिक नहीं हो सकेगी।
- (4) शीघ्र नष्ट होने वाले मालों की स्थिति में फुटपाथ विक्रेता से आवश्यक अर्थ – दंड का भुगतान लेकर उन्हें अपने मालों को तुरंत या फिर अगले चौबीस घंटों में कार्यावधि के भीतर वापस लेने का विकल्प दिया जा सकेगा।

## अध्याय—VIII सामाजिक अंकेक्षण।

24. प्रपत्र एवं रीति, जिसके तहत शहरी फुटपाथ विक्रय समिति की सामाजिक संपरीक्षा कार्यान्वित करने प्रारूप और रीति और अभिलेखों का संधारण।— प्रत्येक शहरी फुटपाथ विक्रय समिति धारा 26 (3) के अधीन सामाजिक संपरीक्षा करवाने के प्रयोजनार्थ त्रिसदस्यीय यूनिट गठित करेगी। सामाजिक संपरीक्षा यूनिट एक स्वतंत्र निकाय होगा।

- (1) सामाजिक संपरीक्षा यूनिट में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:—
  - (क) प्रख्यात शिक्षाविद्, जो समाजशास्त्र के क्षेत्र से ताल्लुक रखते हों;
  - (ख) प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता;
  - (ग) सेवानिवृत्त प्रशासक;  
स्थानीय प्राधिकार द्वारा सहाय्य पर्याप्त अनुसचिवीय स्टाफ, कार्यालय का स्थान और उपस्कर उपलब्ध कराया जाएगा।
- (2) सामाजिक संपरीक्षा तीन वर्षों में कम-से-कम एक बार की जाएगी। उपयुक्त समय पर सामाजिक संपरीक्षा किए जाने की अनुसूची विनिश्चित की जाएगी।
- (3) शहरी फुटपाथ विक्रय समिति, सामाजिक संपरीक्षा प्रक्रिया के आरंभ होने के कम-से-कम एक पखवाड़ा पूर्व सभी सुसंगत सूचनाओं का ब्यौरा उपलब्ध कराएगी, जिसमें निम्नलिखित बातों का समावेश होगा:—
  - (क) अधिनियम के कार्यान्वयन और फुटपाथ विक्रेताओं के स्कीम की स्थिति;
  - (ख) उन वर्षों में हुए शहरी फुटपाथ विक्रय समिति की बैठकों के कार्यवृत्तों का अभिलेख;
  - (ग) सभी रजिस्ट्रीकृत फुटपाथ विक्रेताओं का अभिलेख;
  - (घ) अधिनियम की धारा 11 के अधीन स्थानीय प्राधिकार के समक्ष किए गए अपीलों का अभिलेख;
  - (ङ) अधिनियम की धारा 20 के अधीन शिकायत निवारण समिति के समक्ष लाए गए सभी परिवादों/विवादों का अभिलेख;
  - (च) उन वर्षों में हुए फुटपाथ विक्रेताओं की बेदखली और मालों की जब्ती और पुनर्स्थान निर्धारण की बाबत ब्योरों और उनकी कुल संख्या का अभिलेख;
  - (छ) सामाजिक संपरीक्षा प्रतिवेदनों का अभिलेख, यदि पहले हुआ हो।
- (4) सामाजिक संपरीक्षा यूनिट अधिनियम और स्कीम के कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं पर फुटपाथ विक्रेताओं के साथ बैठकें आयोजित करेगा, जो सामूहिक विचार – विमर्श पर केंद्रित होगा।
- (5) सामाजिक संपरीक्षा यूनिट फुटपाथ विक्रेताओं द्वारा सामना किए गए किसी मुद्दे की बाबत लिखित परिवाद अभिलिखित करेगा।
- (6) सामाजिक संपरीक्षा प्रक्रिया के चरम बिंदु पर, यूनिट लिखित रूप में अपना निष्कर्ष अभिलिखित करेगा।
- (7) सामाजिक संपरीक्षा यूनिट शहरी फुटपाथ विक्रय समिति कार्यालय में सामाजिक संपरीक्षा सार्वजनिक बैठक आयोजित करेगा। शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के सदस्य और स्थानीय प्राधिकार के प्रतिनिधिगण बैठक में भाग लेंगे। क्षेत्र विशेष के फुटपाथ विक्रेता और सार्वजनिक रूप से अन्य व्यक्ति बैठक में भाग ले सकेंगे। सामाजिक संपरीक्षा यूनिट बैठक में अपने निष्कर्षों को पढ़कर सुनाएगा। फुटपाथ विक्रेताओं को इसे प्रमाणित करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा और शहरी फुटपाथ विक्रय समिति भी प्रभावित पक्षकार और जनता को स्पष्टीकरण और/या व्याख्या करते हुए सामाजिक संपरीक्षा में चिह्नित प्रत्येक मुद्दों की बाबत अनुक्रिया करेगा कि क्यों अपरिहार्य कार्रवाई की गई या न की गई।
- (8) सामाजिक संपरीक्षा यूनिट, सर्वसाधारण सूचना द्वारा, सामाजिक संपरीक्षा सार्वजनिक बैठक की समुचित सूचना देगा।
- (9) स्थानीय प्राधिकार अंतरालों, व्यपगतों या विचलनों की स्थिति में सामाजिक संपरीक्षा में प्रत्येक निष्कर्ष पर उत्तरदायित्व नियत करेगा और तुरंत सुधारात्मक या अनुशासनिक कार्रवाई करेगा। विवाद की स्थिति में स्थानीय प्राधिकार द्वारा प्रशासनिक जाँच की जाएगी और कम-से-कम समय में, जो किसी भी स्थिति में एक माह के बाद न हो, तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।
- (10) सामाजिक संपरीक्षा करने की कानूनी अपेक्षा लेखा के सामान्य संपरीक्षा करने के किसी स्वतंत्र पहल को प्रतिबाधित न करेगा
- (11) इस प्रक्रिया में समर्पित सामाजिक संपरीक्षा प्रतिवेदन अभिलेख का भाग बनेगा और शहरी फुटपाथ विक्रय समिति द्वारा उस दिशा में कार्य किया जाएगा। जहाँ भी जो कसर पाई जाए, नियमावली के अनुसार तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सामाजिक संपरीक्षा प्रतिवेदन और कृत कार्रवाई प्रतिवेदन अभिलेख का भाग बनेगा और जनसाधारण सूचनार्थ होगा।



- (12) सामाजिक संपरीक्षा करने का बजट शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के लिए अनुमत प्रशासनिक लागत में से आवंटित किया जाएगा।

### अध्याय—IX प्रकीर्ण।

25. शर्तें, जिनके अधीन निजी स्थानों को प्रतिबंधमुक्त फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र, प्रतिबंधित फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र और गैर फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र के रूप में अभिहित किया जा सकेगा।— जहाँ स्थानीय प्राधिकार विक्रय प्रक्षेत्र के रूप में कोई निजी भूमि की घोषणा का निर्णय लेता हो, यह उस क्षेत्र में अतिरिक्त तल जमीन तालिका या तल क्षेत्रीय अनुपात के रूप में क्षति-पूर्ति संभावनाओं पर विचार करेगा या स्थानीय प्राधिकार के सामान्य विकास नियंत्रण विनियमन की दशा में उसका प्रावधान रखेगा। फुटपाथ विक्रेता को मात्र नीचले तल पर समायोजित किया जाना है।

26. सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिए अनुपालन किए जाने वाले मानकों सहित फुटपाथ विक्रेताओं के लिए शर्तें एवं निबंधन।— (1) संबंधित क्षेत्र के स्थानीय प्राधिकार को स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए इन फुटपाथ विक्रेताओं को एक उचित स्थान उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि वे अपने अपशिष्ट पदार्थों का वहाँ निपटान कर सकें।

- (2) फुटपाथ विक्रेताओं को अपशिष्ट पदार्थों के निपटान हेतु समुचित ढक्कन वाले कूड़ेदानों का इस्तेमाल करना होगा। इस्तेमाल किए गए जल को भी ढक्कन वाले किसी बर्तन में निपटान किया जाएगा।
- (3) स्थानीय प्राधिकार को, जहाँ कहीं संभव हो, फुटपाथ विक्रेताओं को स्वच्छ और ताजा जल तथा सड़क प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित और उपलब्ध करना होगा।
- (4) फुटपाथ विक्रय के खाली स्थानों के नजदीक सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखने के उद्देश्य से जल एवं प्रकाश व्यवस्था सहित साफ और समुचित रूप से निर्मित शौचालयों का उपबंध करने के लिए प्रयास किया जाएगा।
- (5) प्रत्येक फुटपाथ विक्रेता को सेवा अभिलेख – पुस्त रखना होगा और केवल शहरी फुटपाथ विक्रय समिति उसका मूल्यांकन कर सकता है/कर सकेगा। उक्त मूल्यांकन पर आधारित शहरी फुटपाथ विक्रय समिति फुटपाथ विक्रेता को पुरस्कार अधिनिर्णीत कर सकेगा, या फिर उस पर जुर्माना लगा सकेगा।

27. राज्य स्तर पर फुटपाथ विक्रय से संबंधित सभी मामलों के समन्वयन के लिए राज्य नोडल पदाधिकारी का पदनाम।— (1) अभिहित नोडल पदाधिकारी संयुक्त सचिव के अन्यून स्तर का न होना चाहिए।

- (2) नोडल पदाधिकारी विभिन्न क्षेत्र – स्तरीय मुद्दों से स्वयं को भली – भाँति अवगत कराने के लिए स्थानीय प्राधिकारों के साथ कम-से-कम अर्द्धवार्षिक बैठक करेंगे।
- (3) नोडल पदाधिकारी फुटपाथ विक्रेताओं द्वारा सामना किए गए समस्याओं की बाबत उनसे प्रतिपुष्टि – प्रपत्र ले सकेंगे।

28. फुटपाथ विक्रेताओं की बाबत शहरी फुटपाथ विक्रय समिति, स्थानीय प्राधिकार, योजना प्राधिकार और राज्य नोडल पदाधिकारी द्वारा समुचित अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों के संधारण की रीति।—(1) फुटपाथ विक्रेताओं के अभिलेखों को रखने के लिए राज्य सरकारों द्वारा ऑनलाइन सॉफ्टवेयर विकसित किया जाएगा।

- (2) स्थानीय प्राधिकार को ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से सर्वेक्षित फुटपाथ विक्रेताओं के डाटा की प्रविष्टि करनी होगी।
- (3) फुटपाथ विक्रय का प्रमाण-पत्र और पहचान-पत्र ऑनलाईन निकाला जाएगा।

29. समय मुताबिक फुटपाथ विक्रय क्रिया-कलाप करने की रीति —(1) शहरी फुटपाथ विक्रय समिति बाजार की आवश्यकताओं पर आधारित इसे अवधारित करेगा।

- (2) महिला फुटपाथ विक्रेताओं के साथ समय मुताबिक विक्रय क्रिया कलाप के मद्देनजर भेद-भाव नहीं किया जाएगा।

30. प्रतिबंधमुक्त फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र, प्रतिबंधित फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र और गैर फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र के रूप में फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र को अवधारित करने के सिद्धांत।—

- (1) लोगों की आवाजाही की तीव्रता, सड़क की चौड़ाई और वाहन-सवारों तथा पैदल यात्रियों की अधिकता को देखते हुए ही फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र और गैर फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र विनिश्चित किया जाएगा। नगर में प्रतिबंधमुक्त फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र न होंगे और गैर फुटपाथ प्रक्षेत्र काफी न्यूनतम होना चाहिए। शहरी फुटपाथ विक्रय समिति अधोविनिर्दिष्ट तरीके से किसी विशेष सड़क या बाजार को फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र या गैर फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र के रूप में विनिश्चित करेगी और तदनुसार जगह आवंटित की जाएगी।

(2) नगर में सभी प्रतिबंधमुक्त फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र नहीं होंगे। उस क्षेत्र की निर्वाह- क्षमता ही फुटपाथ विक्रेताओं की संख्या की अंतिम सीमा अवधारित करेगा, जिन्हें किसी क्षेत्र में अवस्थित किया जा सकता है। फिर भी, इस क्षेत्र में चलंत फुटपाथ विक्रय पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, यदि फुटपाथ विक्रेता, यातायात और अन्यत्रवासी को बिना बाधा पहुँचाए हुए लगातार एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हों। ऐसी स्थितियों में भी शहरी फुटपाथ विक्रय समिति को खास आवाजाही वाले क्षेत्र और उस क्षेत्र की एक तिहाई धारण -क्षमता को ध्यान में रखते हुए ऐसे चलंत फुटपाथ विक्रेताओं को स्थान सुविधा दिए जाने के लिए उनकी कुल संख्या पर विनिश्चय करना है, अन्यथा इस बात की पूरी संभावना बनी रहेगी कि चलंत फुटपाथ विक्रेता अपनी दुकानदारी के दौरान एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहने के कारण वाहन मार्ग में बहुधा आकर यातायात संचालन में व्यवधान उत्पन्न करते रहेंगे।

(3) प्रतिबंधित फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र निम्नलिखित रीति से सड़क की चौड़ाई से जोड़े जाएंगे:-

- (क) 3.5 मीटर से कम चौड़ी सड़क पर कोई भी स्थायी फुटपाथ विक्रय नहीं होगा।  
 (ख) 3.5 मीटर से 6.0 मीटर के बीच की चौड़ी सड़क पर कोई भी स्थायी फुटपाथ विक्रय नहीं होगा। फिर भी, फुटपाथ विक्रय उस स्थिति में अनुमत होगी, जब ऐसे सड़क को गैर वाहन परिचालन सड़क के रूप में घोषित किया जाए। ऐसी परिस्थिति में फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र 2.0 मीटर तक सीमित होगा।  
 (ग) छः मीटर से नौ मीटर के बीच की चौड़ी सड़क पर कोई भी स्थावर फुटपाथ विक्रय नहीं होगा। फिर भी, फुटपाथ विक्रय उस स्थिति में अनुमत होगी, जब ऐसे सड़क को गैर वाहन परिचालन सड़क के रूप में घोषित किया जाए।  
 (घ) 12 मीटर से 24 मीटर के बीच की चौड़ी सड़क पर केवल एक तरफ स्थावर फुटपाथ विक्रय होगा, जबकि 30 मीटर या उससे अधिक चौड़ी सड़क पर दोनों तरफ स्थावर फुटपाथ विक्रय होगा।  
 (ङ) ऐसी सड़क के प्रत्येक अभिहित फुटपाथ विक्रय क्षेत्र की धारण शक्ति पर विचार करते हुए फुटपाथ विक्रेताओं की संख्या विनिश्चित की जाएगी।  
 (च) व्यवधानरहित वाहन परिचालन और पैदल यात्री आवागमन के मद्देनजर यातायात पुलिस से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेने के बाद ही ऐसे स्थावर फुटपाथ विक्रय की अनुमति दी जाएगी। यदि अपेक्षित हो, तो सड़क के किनारे वाहन पड़ाव को ऐसे क्षेत्र में प्रतिबंधित किया जाएगा, जहाँ फुटपाथ विक्रय अनुमत हो।  
 (छ) यातायात संचालन और पैदल यात्री आवागमन को देखते हुए चलंत फुटपाथ विक्रय अनुमत किया जाएगा।  
 (ज) स्कीम के लिये एक परामर्शी सड़क रूपरेखा अनुसूची के रूप में संलग्न है।

(4) गैर फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र निम्नलिखित होंगे।- सचिवालय, जिला समाहरणालय, जिला पंचायत के कार्यालय, नगर निगम, नगरपालिका, नगर पंचायत, न्यायालय, छावनी बोर्ड और राज्य पुरातत्वीय स्मारकों जैसे महत्वपूर्ण संस्थानों के निकट एवं दो या दो से अधिक सड़कों के पारगामी किसी भी तरफ एवं रेल समपार के दोनों तरफ तथा स्थानीय प्राधिकार द्वारा घोषित किसी ऐतिहासिक धरोहरों एवं फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र के बीच की दूरी तय करने का निर्णय शहरी फुटपाथ विक्रय समिति के द्वारा विशिष्ट क्षेत्र के संदर्भ में स्वविवेक से लिया जा सकेगा।

31. फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्रों की धारण क्षमता को अवधारित करने के सिद्धांत और व्यापक जनगणना एवं सर्वेक्षण की जिम्मेवारी लेने की रीति।-

- (1) अधिनियम की धारा (3) के अधीन वार्ड/प्रक्षेत्र के फुटपाथ विक्रेताओं की 2.5% जनसंख्या को धारण - क्षमता के अनुसार समायोजित किया जाएगा।  
 (2) किसी फुटपाथ विक्रय प्रक्षेत्र की धारण - क्षमता उस फुटपाथ विक्रय क्षेत्र के कुल क्षेत्र द्वारा विभाजित फुटपाथ विक्रय स्थल के अनुसार होगा। शहरी फुटपाथ विक्रय समिति द्वारा व्यक्तिगत फुटपाथ विक्रेताओं को आवंटित किए जानेवाले क्षेत्र के लिए मानदंड निम्नवत रखे जाएंगे-  
 (i) 1.6 मीटर X 1.2 मीटर लंबाई-चौड़ाई के अधिकतम 2 वर्गमीटर क्षेत्र को फुटपाथ विक्रय क्षेत्र के रूप में प्रत्येक फेरीवाला/फुटपाथ पर बेचने वाले को उपलब्ध कराया जाएगा।  
 (ii) स्टालों/टेला गाड़ियों के सामने 1.0 मीटर चौड़ाई का रास्ता विस्तार के रूप में सुरक्षित रहेगा, ताकि ग्राहक/उपभोक्ता वहाँ खड़े रह सकें या माल खरीद सकें।  
 (iii) सड़क की चौड़ाई को देखते हुए ऐसे विस्तारित जगह के सामने 1.0/2.0 मीटर का पद-विचरण स्थल/फुटपाथ पैदल यात्रियों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।  
 (iv) किसी भी स्थिति में फुटपाथ विक्रय के लिए गाड़ी-वाहन का उपयोग किए जाने की अनुमति न दी जाएगी।

- (v) यदि ऐसा लगे कि सड़क की चौड़ाई काम भर है, तो सड़क के दोनों तरफ फुटपाथ विक्रय की अनुमति दी जा सकेगी।
- (vi) सड़क के किसी जंक्शन/निकास/प्रवेश या रेल समपार से 50 मीटर की दूरी तक किसी भी प्रकार के फुटपाथ विक्रय क्रियाकलाप की अनुमति नहीं दी जाएगी।

**32. पुनर्स्थापन निर्धारण के मानदंड—**

- (1) जहाँ तक संभव हो, पुनर्स्थापन निर्धारण से बचा जाना चाहिए, जब तक कि, प्रश्नगत भूमि के लिए स्पष्ट एवं त्वरित आवश्यकता न हो।
- (2) प्रभावित फुटपाथ विक्रेताओं या उनके प्रतिनिधियों को पुनर्स्थापन परियोजना के योजनाकरण एवं कार्यान्वयन में लगाया जाएगा।
- (3) शहरी फुटपाथ विक्रय समिति बाजारों के प्रतिनिधियों से संवाद स्थापित करेगी।
- (4) पुनर्वास परियोजना के कार्यान्वयनाधीन पुनर्स्थापन निर्धारण के लिए पारस्परिक सहमति के स्थान पर विचार किया जाएगा।
- (5) प्रभावित फुटपाथ विक्रेताओं का पुनर्स्थापन निर्धारण किया जाएगा, ताकि उनकी जीविका और जीवन-स्तर में सुधार हो या कम-से-कम उन्हें पुनर्प्राप्त कर लें, उस वास्तविक अर्थ में जो बेदखली से पूर्व की स्थिति थी।
- (6) नवीन आधारभूत संरचना विकास परियोजनाओं द्वारा सृजित जीविका के अवसरों से विस्थापित फुटपाथ विक्रेताओं को समायोजित करने का प्रयत्न किया जाएगा, ताकि वे नवीन आधारभूत संरचना द्वारा सृजित जीविका के अवसरों से लाभ उठा सकें।
- (7) परिसंपत्तियों की क्षति से बचा जाएगा;
- (8) हक का अंतरण या भूमि का अन्य हित ऐसी भूमि पर और ऐसे पुनर्स्थान निर्धारण पर फुटपाथ विक्रेताओं के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा और ऐसे भूमि-अंतरण के परिणामस्वरूप कोई भी पुनर्स्थान निर्धारण इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा;
- (9) प्राकृतिक बाजार, जहाँ पचास वर्षों से अधिक फुटपाथ विक्रेताओं ने कारबार किया हो, को विरासती बाजार के रूप में घोषित किया जाएगा और ऐसे बाजारों में फुटपाथ विक्रेताओं का पुनर्स्थान निर्धारण नहीं किया जाएगा;
- (10) नगरपालिका निकाय ऐसे बाजारों की सूची तैयार करेगा और उन्हें विरासती बाजार के रूप में घोषित करेगा। नगरपालिका निकाय पर्यटन विभाग के सहयोग से ऐसे बाजार में ऐसे तत्वों को आत्मसात करते हुए पर्यटक बाजारों के रूप में ऐसे बाजारों को संवर्द्धित करेगा, जिससे ऐसे बाजार में स्थानीय रंगत अपनी विशिष्टियों के साथ झलकता रहेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
चैतन्य प्रसाद,  
सरकार के प्रधान सचिव।

**अनुसूची**  
**फुटपाथ विक्रय जगह सहित मार्ग रूपांकन**

क्र० सं०	मार्ग की चौड़ाई (मीटर में)	फुटपाथ	फुटपाथ विक्रय जगह	सेवा मार्ग	साइकिल का रास्ता	वाहन का रास्ता	केन्द्रीय हाता	वाहन का रास्ता	साइकिल का रास्ता	सेवा मार्ग	फुटपाथ विक्रय जगह	फुटपाथ	फुटपाथ विक्रय की स्थिति	संप्रतिबंध अनुमति
1	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	अनानुमत	
		0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	अनुमत	गैर-वाहन परिचालन क्षेत्र
2	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	अनानुमत	
		0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	अनुमत	गैर-वाहन परिचालन क्षेत्र
3	9.0	1.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	1.0	अनानुमत	
		1.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.5	0.0	0.0	0.0	1.0	अनुमत	सड़क के एक तरफ

क्र० सं०	मार्ग की चौड़ाई (मीटर में)	फुटपाथ	फुटपाथ विक्रय जगह	सेवा मार्ग	साईकिल का रास्ता	वाहन का रास्ता	केन्द्रीय (अ) हाता	वाहन का रास्ता	साईकिल का रास्ता	सेवा मार्ग	फुटपाथ विक्रय जगह	फुटपाथ	फुटपाथ विक्रय की स्थिति	सप्रतिबंध अनुमति
4	12.0	1.0	3.0	0.0	0.0	3.5	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	1.0	अनुमत	एक तरफ
5	15.0	1.0	3.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	1.0	अनुमत	एक तरफ
6	10.0	1.0	3.0	0.0	0.0	6.0	1.0	6.0	0.0	0.0	0.0	1.0	अनुमत	एक तरफ
7	24.0	1.5	3.0	0.0	0.0	8.5	1.0	8.5	0.0	0.0	0.0	1.5	अनुमत	एक तरफ
8	30.0	1.5	3.0	0.0	1.0	9.0	1.0	9.0	10	0.0	3.0	1.5	अनुमत	दोनों तरफ
9	36.0	2.0	3.0	0.0	1.5	11.0	1.0	11.0	1.5	0.0	3.0	2.0	अनुमत	दोनों तरफ
10	40.0	2.0	3.0	0.0	1.5	13.0	1.0	13.0	1.5	0.0	3.0	2.0	अनुमत	दोनों तरफ
11	60.0	3.0	4.0	5.0	2.0	15.0	2.0	15.0	2.0	5.0	4.0	3.0	अनुमत	दोनों तरफ

नोट: -

- ये परिगणनाएँ वाहन परिचालन यातायात की क्षमता धारण के लिए यातायात अनुभाग के अनुमोदन के अधीन है।
- दो भागों से होने वाले यातायात के लिए न्यूनतम 7 मीटर जगह अपेक्षित है।
- फुटपाथ विक्रय के लिए उपलब्ध न्यूनतम क्षेत्र - 3 मीटर
- पैदल यात्रियों के आवागमन के लिए न्यूनतम जगह की आवश्यकता - 1 मीटर

15 फरवरी 2017

सं० 04/SV(NULM)-04/2015-416/ न०वि०एवंआ०वि०, सं० 04/SV(NULM)-04/2015-415/न०वि०एवं आ०वि०, दिनांक 15 फरवरी 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
चैतन्य प्रसाद,  
प्रधान सचिव।

*The 15<sup>th</sup> February 2017*

**Bihar Street Vendors (Protection of livelihood and regulation of Street Vending) Schemes'2017**  
No. 04/SV(NULM)-04/2015-415/UD&HD—In exercise of the powers conferred by Section 38 of the Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014 (Central Act 7 of 2014), the State Government after consultation with the Urban Local Bodies and Town Vending Committees do hereby make the following Scheme for the purpose of the said Act, namely :-

#### CHAPTER-I PRELIMINARY

1. **Short title and commencement.**— (1) This Scheme may be called **The Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Scheme-2017**.

(2) It shall come into force on such date, as State Government may, by notification, fixed and different dates may be fixed different Municipalities.

2. **Definitions.** - (1) In this Scheme, unless the context otherwise requires:-

- (a) "Act" means the Street Vendors(Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014( Central Act 7 of 2014);
- (b) "appropriate Government" means the Government of Bihar;

- (c) **”local authority”** means a Municipal Corporation or a Municipal Council or a Nagar Panchayat, by whatever name called, [or the Cantonment Board, or as the case may be, a civil area committee appointed under section 47 of the Cantonment Act, 2006 [or such other body entitled to function as a local authority in any city or town to provide civic services and regulate street vending in that city or town;
- (d) **”notification”** means a notification published in the Official Gazette and the term “notify” shall be constructed accordingly;
- (e) **”street vendor”** means a person engaged in vending of articles, goods, wares, food items or merchandise of everyday use or offering services to the general public, in street, lane, side walk, footpath, pavement, public park, or any other public place or private area, from a temporary built up structure or by moving from place to place and includes hawker, peddler, squatter and all other synonymous term which may be local or region specific; and the words “street vending” with their grammatical variations and cognate expressions, shall be constructed accordingly;
- (f) **”stationary vendors”** means street vendors who carry out vending Activities on regular basis at a specific location;
- (g) **”mobile vendors”** means street vendors who carry out vending Activities in designated area by moving from one place to another place vending their goods and services;
- (h) **”festive market”** means a market where sellers and buyers have traditionally congregated for the sale and purchase of products or services during festival season of the city or town and has been determined as such by the local authority on the recommendations of the Town Vending Committee;
- (i) **”heritage market”** means a market which has completed more than fifty years in one place where sellers and buyers have traditionally congregated for the sale and purchase of products or services and has been determined as such by the local authority on the recommendations of the Town Vending Committee;
- (j) **”natural Market”** means a market where sellers and buyers have traditionally congregated for the sale and purchase of products or services and has been determined as such by the local authority on the recommendations of the Town Vending Committee;
- (k) **”niche market”** means a market where sellers and buyers have traditionally congregated for the sale and purchase of niche products or services and has been determined as such by the local authority on the recommendations of the Town Vending Committee;
- (l) **”night bazaar”** means a bazaar where sellers and buyers have traditionally congregated for the sale and purchase of products or services after evening i.e. during night and has been determined as such by the local authority on the recommendations of the Town Vending Committee;
- (m) **”seasonal market”** means a market where sellers and buyers have traditionally congregated for the sale and purchase of products or services during specific seasons and has been determined as such by the local authority on the recommendations of the Town Vending Committee;

- (n) **”weekly market”** means a market where sellers and buyers have weekly congregated for the sale and purchase of products or services and has been determined as such by the local authority on the recommendations of the Town Vending Committee;
- (o) **”Town Vending Committee”** means the body constituted by the appropriate Government under Section 22 of the Act;
- (p) **”vending zone”** means an area or a place or a location designated as such by the local authority, on the recommendations of the Town Vending Committee, for the specific use by street vendors for the street vending and includes footpath, side walk, pavement, embankment, portions of a street, waiting area for public or any such place considered suitable for vending Activities and providing services to the general public.
- (q) **” Plan”** means the Plan made under First Schedule of Section 22 of the Act;
- (r) **”planning authority”** means an Urban Development Authority or any other authority in any city or town designated by the appropriate Government as responsible for regulating the land use by defining the precise extent of areas for any particular Activity in the master plan or development plan or zonal plan or layout plan or any other spatial plan under the Town and Country Planning Act or the Urban Development Act or the Municipal Act, which is legally enforceable for the time being as the case may be;
- (s) **”public purpose”** includes in the context of the Act(i) widening of roads, streets, lanes;(ii) shifting the alignment of roads, streets, lanes;(iii) erecting flyovers with or without clover leaves and slip down roads; (iv) erecting underpasses; (v) development of land owned by public authorities for some public projects; (vi) laying of water, or sewer pipe lines;(vii) erecting intermediate pumping stations for the services; (viii) any project related with public transport like BRTS, Metro, etc.; (ix) erection of Economically Weaker Section(EWS) Housing; (x) Creation Parks, Gardens and Recreational Area; (xi) Conservation of any eco system resource in that area and (xii) Any other development work taken by the local authority, the beneficiary of which will be the community at large.
- (t) **”Scheme”** means the Scheme made under Second Schedule of section 38 of the Act;
- (u) **”Section”** means section of the Act;
- (v) **”holding capacity”** means the maximum number of street vendors who can be accommodated in any vending zone and has been determined as such by the local authority on the recommendations of the Town Vending Committee;
- (w) **”Grievance Redressal Committee”** means a committee constituted by the Government of Bihar under sub- section (1) of section 20 of the Act;
- (2) Words and expressions defined in the Act and used but not defined in this scheme shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Act.

**CHAPTER –II**  
**MANNER OF CONDUCTING SURVEY**

3. **Process of Survey.**—(1) The Town Vending Committee shall conduct the survey itself or go it done by any suitable agency.

(2) Adequate publicity of the proposal shall be given in the following manner:-

- (i) On its websites
- (ii) by publishing in any two prominent local newspapers published in the local language of the area
- (iii) by placing it on the notice board of the office, and
- (iv) by placing a copy in any conspicuous place in the local market within the jurisdiction of the local authority

(3) Camps may be organized for the survey of street vendors after prior information

4. The survey outcome shall be available in the digital format

5. In the survey report the street vending activity carried on from the carriage way shall be specifically mentioned and marked on the map. Similarly, mode of vending shall also be clearly indicated. Manner of vending may be any of the following:-

- (1) Push cart/ motorized vehicle
- (2) Floor spread
- (3) Rack and hanging frame mode

6. Subject to the provisions of the Act and the provisions contained in the Scheme, the Town Vending Committee shall, as far as practicable, ensure that all existing Street Vendors identified in the survey conducted under section-3 are accommodated in the vending zone.

**CHAPTER-III**  
**ISSUE OF IDENTITY CARD AND CERTIFICATE OF VENDING**

7. **The period within which Identity Card and certificate of vending shall be issued to the street vendors identified under survey.**— The street vendor identified by the survey shall be issued Identity card and certificate of vending within a maximum period of six [6] months' time from the date of survey.

8. **The terms and conditions subject to which Identity card and certificate of vending may be issued to a street vendor including to those persons who wish to engage on street vending during the intervening period of two surveys.**—The criterion under which Identity Card and certificate of vending to street vendors will be issued:-

- (i) Name shall include in the survey carried out by the TVC.
- (ii) shall be street vendor only and will not be engaged in any other occupation.
- (iii) No other parallel vending site in any other place by the same persons. However his/her spouse and any child above 14 years of age can have a different vending site.
- (iv) shall engage the vending by him or her though family or other people (if he/she has completed 14 years) can be involved.
- (v) Any street vendor who has completed the age of 14 years of age.
- (vi) New Street vendor who wish to carry on street vending during the intervening period of two surveys, has to apply through Town Vending Committee for the Identity card and vending certificate.

9. *The form and manner in which the certificate of vending shall be issued to a street vendor;*

- (i) Photo of the vendor-
- (ii) Name of the vendor-
- (iii) Name of the spouse or dependent child if involved in vending with the vendor-
- (iv) Age and Sex of the person/s whose photo appears-
- (v) Address of residence-
- (vi) Category of Vending (Mobile/Stationary/Natural/Weekly etc.)-
- (vii) Name of Vending Place (whether it is historical place, park, market, in front of school/college/hospital/bus stand or malls etc.)-
- (viii) Name of the Municipal body-
- (ix) Date of Issuing Vending Certificate-
- (x) Validity (Since the law provides for survey every five year, the certificate of vending should also be issued for five year)-
- (xi) Unique Registration Number-

10. *The form and manner of issuing identity cards to street vendors;*

- (i) Name of the vendor-
- (ii) Age-
- (iii) Sex-
- (iv) Address of residence-
- (v) Address of the vending site-
- (vi) Photo-
- (vii) Phone Number-
- (viii) Category of vending-
- (ix) Municipal ward or zone number-
- (x) Police station-
- (xi) Validity period-
- (xii) Signature of the authority with seal-

11. *The period of validity of Identity card and certificate of vending.*— The Identity card and vending certificate shall be renewed after every five [5] years through a simple process of paying the fees. The deposit of fees and issue of receipt shall be considered to be adequate proof of the renewal of vending certificate.

#### CHAPTER –IV

#### RENEWAL, SUSPENSION AND CANCELLATION OF CERTIFICATE OF VENDING

12. *The period for which and the manner in which a certificate of vending may be renewed and the fees for such renewal. -*

- (1) The vending certificate may be renewed after every five [5] years .It shall be a simple process of submitting the fees and renewing the vending certificate.  
The Town Vending Committee will put up the list of the vendors whose due dates for renewal falls within a period of two months. In the said paper the amount as well as the places or institution where it can be paid can be indicated.
- (2) TVC will publish a list of defaulter street vendors who has failed to pay the renewal fees of vending certificate.
- (3) The renewable fees of the vending certificate shall not be less than Rs.500.



- (4) 1 (One) month's period will be granted for the payment of renewal fees without any penalty.
- (5) In case of loosing Identity Cards or Certificate of vending, TVC can issue the duplicate Identity card or Certificate of vending with the cost of Rs. 50/ to street vendors.

**13. The manner in which the certificate of vending may be suspended or cancelled.—**

The TVC shall impose fine and a warning on the street vendor found guilty of breach of conditions laid down in the vending certificate. The following will be the breach of conditions:-

- (i) If he/she caring out vending squatting/ hawking in the area/market other than mentioned in the vending license.
- (ii) Misrepresented the age (minimum age is 14 years) for eligibility to get vending certificate;
- (iii) If the area allotted has been increased or unauthorized occupying additional area.
- (iv) If no registration has be done under FSSAI in case of food vendors.
- (v) If any permanent structure has been constructed on the allotted place.
- (vi) If certificate of vending is sold or leased out to any other person.
- (vii) If the vending certificate has not been renewed after the prescribed period is over.
- (viii) Any street vendor who has employed any child below 14 years of age [under Child Labour (Prohibition and Bye-laws [Regulation]) Act, 2005 will be given a warning by the TVC. But failing that their vending certificate will be cancelled.
- (ix) Any street vendor who is guilty of misbehaviour with women vendor will be given a warning based on the written complaint filed by the aggrieved.
- (x) The TVC should make a committee [Headed by a woman official] to take into account the Domestic Violence Act, 2005, Harassment at workplace (Prevention, Prohibition and redressal) Act-2013 and also Indian Penal Code to protect women at work place.

**CHAPTER-V**

**CATEGORIES OF STREET VENDORS AND FEES**

**14. The categories of street vendors.—** *The vendors can also be categorized as :*

- (i) Stationary;
- (ii) Mobile;
- (iii) Any other which may the state Govt. provide for.

**15. The other categories of persons for preference for issue of Identity card and certificate of vending .—** TVC will accord priority for senior citizen, physically challenged, single mothers and widows.

**16. The vending fees to be paid on the basis of category of street vending, which may be different for different cities;**

The vending fees shall be according to the category of the street vendors and the status of the market.

[Explanation-Income potential differs from area to area. High footfall areas offer high vending opportunity compared to lean footfall areas. Therefore it is only correct to fix

the fees at different rates for different categories of vending zones. Similar will be the arguments for varied rates for cities and towns of different categories.]

TVC shall have to fix fees/levies depending on the footfall of the area but fees shall be minimum Rs.150 and maximum Rs.1500 per month. Every year a minimum 10% increase shall be imposed. Local authority can collect vending fee annually if it deems fit.

**17. The manner of collecting, through banks, counters of local authority and counters of Town Vending Committee, vending fees, maintenance charges and penalties for registration, use of parking space for mobile stalls and availing of civic services:-**

Every TVC will have a bank account and street vendors will deposit the money per month or year into that account along with the details in the prescribed form. An annual audit of the account will be carried out by the TVC. The local authority concerned is free to make its own any alternative arrangement for collection for TVC.

## CHAPTER-VI

### RELOCATION AND EVICTION OF STREET VENDORS

**18. The public purposes for which a street vendor may be relocated and the manner of relocating street vendor;**

- (1) Any project of public purpose, requiring temporary or permanent shifting of the street vendors in the project related area, the concern authorities shall consider following two points for relocation:
  - (i) During the time of construction/development the street vendors may be adjusted in a nearby place temporarily or permanently.
  - (ii) After completion of the project, the street vendors may be adjusted in the same place of public purpose area for vending to the extent possible but it is not compulsory/mandatory.
- (2) Rehabilitation of street vendors under any public purpose would require taking of the following steps:-
  - (a) Give an estimate of footfall status in an area where from the vendors are to be shifted.
  - (b) Total number of vendors to be shifted.
  - (c) Footfall status of the alternative sites.
  - (d) Carrying capacity of the alternative sites.
  - (e) Likely availability of vending space after the project is completed.
  - (f) Temporary allotment of sites for shifting the vendors may be done by lots.
  - (g) In case number of the vendors in the original site is more than the number which could be accommodated after the project is completed, allotment by lot can be adopted.
  - (h) The vendors who were carrying on business from a government land can either be placed in a plot owned by the public authority or can be organized on the road depending on the availability.

**19. The manner of evicting a street vendor.-**

- (1) TVC should bring in its agenda and discuss the issue of eviction of street vendors 2 months prior to the issuance of 1 month notice of eviction, so that a survey can be conducted to identify an equally vending site for the street vendors
- (2) The 1 month written notice should be served via registered post prior eviction in the name of street vendor. It can be served personally also.

- (3) In case registered post comes back undelivered, the said notice should be posted on the area where from he is carrying on his vending. That should be considered as the service of the notice.

**20. The following shall be the manner of giving notice for eviction of a street vendor.—**

- (1) One month notice prior eviction under Section 18 of the Act.  
 (2) The notice of eviction should be in the name of the street vendor who is getting evicted via registered post or personally.

**21. The manner of evicting a street vendor physically on failure to evict.—**

- (1) Under Section 18 of the Act the street vendor who fails to move out on the expiry of the eviction notice period shall be liable to pay for everyday default.  
 (2) The default amount or the penalty payable by the street vendor may extend up to Rs. 250 only. However, the penalty fees will not exceed the value of the goods seized.

**CHAPTER-VII  
SEIZURE OF GOODS**

**22. The manner of seizure of goods by the local authority, including preparation and issue of list of goods seized.—**Under Section-19 of the Act, following steps may be followed with regard to seizure of goods:

- (i) Only the authorized person from the local authority will conduct seizure of goods.  
 (ii) The list of goods seized will be made by the concerned authority and the same will be duly signed by the concerned authority.  
 (iii) The street vendor, whose goods are seized, will be given proper receipt by the authority.

**23. The manner of reclaiming seized goods by the street vendors and the fees for the same.-**

- (1) Under Section 19(2) the local authority may release the perishable seized goods same day of the such seizure and in case of non-perishable goods within 2 working days.  
 (2) The fees to be paid by the street vendor for reclaiming the goods may not exceed the value of the total seized goods of the vendor.  
 (3) In case of vending without certificate then the charge should not exceed Rs. 500/- for reclaiming seized goods  
 (4) In case of perishable goods, the vendor may be given option to take the goods back immediately by paying necessary penalty or within the working period in the next 24 hours.

**CHAPTER-VIII  
SOCIAL AUDIT**

**24. The form and the manner to carry out social audit of the Activities of Town Vending Committee and maintenance of records.—** Every TVC shall constitute a three member unit for the purpose of carrying out social audit under Section 26(3). The social audit unit shall be an independent body.

- (1) The social audit unit shall consist of the following:-  
 (a) An eminent Academician in the field of Sociology  
 (b) An eminent Social Activist  
 (c) A Retired Administrator

Supporting adequate Secretariat Staff with office space and equipment should be provided by the local authority

- (2) The social audit shall be carried out at least once in three years. The schedule for conduct of the social audit shall be determined at an appropriate time
- (3) The TVC shall provide details of all relevant information, at least a fortnight before the social audit process commences. This shall include the following:-
  - (a) Status of implementation of the Act and the Scheme for Street Vendors.
  - (b) A record of the minutes of the meetings of the TVC conducted in those years.
  - (c) Record of all registered street vendors.
  - (d) Records of appeals made before the local authority under Section 11 of the Act.
  - (e) Record of all grievances/disputes brought before the Grievance Redressal Committee under Section 20 of the Act.
  - (f) Record of the total number and details of evictions and confiscation of goods and relocation of street vendors taken place in those years.
  - (g) Records of social audit reports, if any, taken place previously.
- (4) The social audit unit shall conduct meetings and focussed group discussions with street vendors on various aspects of the implementation of the Act and the Scheme.
- (5) The social audit unit shall record in writing grievances of street vendors on any issue faced by them.
- (6) At the culmination of the social audit process, the unit shall record its findings in writing.
- (7) The social audit unit shall hold a social audit public meeting at the TVC office. TVC members and representatives of the local authority shall attend the meeting. Street vendors of the particular area and other persons from the public may participate in the meeting. The social audit unit shall read out its findings at the meeting. Street vendors shall be encouraged to testify and the TVC shall respond to each of the issues identified in the social audit by giving clarification and/or explanation to the affected party and the public as to why a certain action was taken or not taken.
- (8) The social audit unit shall give adequate notice of the social audit public meeting by a public notice.
- (9) The local authority shall on each finding of the social audit in cases of gaps, lapses or deviations fix responsibility and shall take immediate corrective or disciplinary action. In case of a dispute, an administrative enquiry shall be conducted by the local authority and action taken accordingly in the shortest time possible and in any case not later than a month.
- (10) The statutory requirement of conducting social audit shall not preclude any independent initiative to carry out normal audit of accounts.
- (11) Social audit reports submitted in this process shall form part of the record and shall be responded to by the TVC. Where shortcomings are found immediate action shall be taken as per these rules. The social audit report as well as the action taken report shall form part of the record and shall be public information.
- (12) The budget for conducting social audit shall be allocated from amongst the administrative cost allowed for TVC.

**CHAPTER-IX  
MISCELLANEOUS**

**25. The conditions under which private places may be designated as restriction-free-vending zones, restricted – vending zones and no-vending zones.—** Where the local authority decides to declare any private land as the vending zone, it shall take into consideration the possibility of offering compensation in form of additional floor space Index (FSI) or Floor Area Ratio (FAR) than prevailing in that area or Transferrable Development rights (TDR) in case the General Development Control Regulations (DGCR) of the local authority has got the provisions of it. The street vendors are to be accommodated in the ground level only.

**26. The terms and conditions for street vending including norms to be observed for up keeping public health and hygiene.—**

- (1) The Local Authority of the concerned area will provide these vendors a proper place to dispose off their waste materials in order to maintain a hygienic environment.
- (2) The street vendors will use proper covered dustbins to dispose off the waste materials. The used water will also be disposed off in a covered container.
- (3) The Local Authority will ensure and provide the street vendors clean and fresh water along with street light facility wherever it is possible.
- (4) Attempt may be made to provide clean and properly constructed toilets with water and electricity facility in order to maintain public health and hygiene near the street vending strips.
- (5) Every street vendor will have service record book and TVC only can/ will access that. Based on that TVC can award prize/impose fine upon the vendor.

**27. The designation of State Nodal Officer for co-ordination of all matters relating to street vending at the state level.—**

- (1) The designated Nodal Officer should not be below the Joint Secretary level.
- (2) The nodal officer shall have at least a half yearly meeting with the Local Authorities in order to get himself acquainted with various field level issues.
- (3) The nodal officer may have the feedback forms from the street vendors about the problems faced by them.

**28. The manner of maintenance of proper records and other documents by the Town Vending Committee, Local Authority, planning authority and state nodal officer in respect of street vendors-**

- (1) On –line software will be developed by the state governments for keeping the records of the street vendors.
- (2) The local authority must enter the data of the surveyed street vendors through on-line process.
- (3) The certificate of vending and identity card must be on-line generated.

**29. The manner of carrying out vending Activities on time-sharing basis.-**

- (1) The TVC will determine it depending on the market needs.
- (2) Women vendors will not be discriminated while allotting time - sharing vending Activities.

**30. The principles for determining of vending zones as restriction-free-vending zones, restricted-vending zones and no- vending zones:-**

- (1) An intensity of foot fall, Road width and Density of the vehicular and pedestrian movement shall be the cornerstone for deciding vending and no vending zone. There shall be no restricted free vending zones in the city and no vending zone

should be very minimal. The TVC shall decide the particular street or market as vending zone or no vending zone as specified below and accordingly the space should be allotted.

- (2) There shall not be any totally **restriction- free-vending zones** in the city. Carrying capacity of an area would put up the ultimate limit on the number of street vendors which can be positioned in any area. However, there shall not be any restriction on mobile vending in this area if vendors continuously move without affecting traffic and commuter movements. In such cases the TVC has to decide the total number of such mobile vendors can be accommodate after taking into account the area of significant footfall and 1/3<sup>rd</sup> of the holding capacity of the area. Otherwise there is every chance of mobile vending itself creating problem for the traffic movement, as the mobile vending invariably takes place from the carriage way.
- (3) ***Restricted vending zones will be linked with the road width in the following manner:-***
  - (a) There shall not be any stationary street vending on a road having width less than 3.5 meters.
  - (b) There shall not be any stationary street vending on a road having width between 3.5 meters to 6 meters. However, street vending shall be allowed if such road is declared as no vehicular road. In such cases, the street vending shall be restricted to 2.0 metre.
  - (c) There shall not be any stationary street vending on a road having width between 6 meters to 9 meters. However, street vending shall be allowed if such road is declared one way vehicular road.
  - (d) There shall be only one side stationary street vending on a road having width between 12 meters to 24 meters while both side stationary vending shall be allowed on a road having road width of 30 meters and above.
  - (e) Number of street vendors shall be decided by considering holding capacity of each designated vending area on such a road.
  - (f) Such stationary vending shall be allowed after taking the clearance from traffic police regarding the smooth vehicular and pedestrian movement. If required, road side parking shall be banned in such area where street vending is allowed.
  - (g) Mobile vending shall be allowed on such road looking to the traffic and pedestrian movement.
  - (h) A suggestive road design is provided in the annexure appended to the scheme
- (4) ***The following shall be no vending zone.***—The Town Vending Committee may decide the distance to be kept free from Street Vending near the important institutions like Secretariat and District Collectorate, Offices of the District Panchayat, Municipal Corporation, Municipality, Nagar Panchayat, Court, Cantonment Board and State Archaeological Monuments attracting a high footfall, any crossing of two or more roads on all sides or both sides of the railway crossing and any declared heritage structure by the local authority at its discretion taking into account the specifics of the area of concerned.

**31. The principles for determining holding capacity of vending zones and the manner of undertaking comprehensive census and survey.-**

- (1) Under section 3 of the Act 2.5% of the population of street vendors of a ward/ zone will be accommodated as per the holding capacity.
- (2) The holding capacity of a vending zone will be according to the vending site divided by the total area of the vending area.
- (3) **For Areas to be allotted to individual vendors Criterion may be kept by the TVC as follows:-**
  - (i) A maximum of 2 sq. mts area as 'vending area' shall be provided to each vendor/hawker with dimension of 1.6 meter x 1.2 meter.
  - (ii) Passage of 1.0 meter width in front of stalls/ push carts shall be reserved as 'extension' for consumers/ users to stand or buy goods.
  - (iii) A walkway/footpath of 1.0/2.0 meters width shall be provided for pedestrians, in front of extension space depending on the road width.
  - (iv) In no case, the carriageway shall be allowed to be used for street vending.
  - (v) If the width of road permits, street vending may be allowed on both sides of the road.
  - (vi) No vending Activity shall be allowed at a distance of 50 meters from any junction/exit/entry of road or the railway crossing.

**32. Criteria of relocation.-**

- (1) Relocation will be avoided as far as possible, unless there is clear and urgent need for the land in question;
- (2) Affected vendors or their representatives shall be involved in planning and implementation of the rehabilitation project;
- (3) The TVC shall engage in the dialogues with the representatives of the markets.
- (4) Mutually agreed place for relocation should be considered under the implementation of the rehabilitation project.
- (5) Affected vendors shall be relocated so as to improve their livelihoods and standards of living or at least to restore them, in real terms to pre-evicted levels;
- (6) Livelihood opportunities created by new infrastructure development projects may try to accommodate the displaced vendors so that they can make use of the livelihood opportunities created by the new infrastructure;
- (7) Loss of assets shall be avoided;
- (8) Any transfer of title or other interest in land shall not affect the rights of street vendors on such land, and any relocation consequent upon such a transfer shall be done in accordance with the provisions of this Act;
- (9) Any Natural markets where street vendors have conducted business for over fifty years shall be declared as heritage markets, and the street vendors in such markets shall not be relocated;
- (10) The Municipal body shall prepare a list of such markets and declare them as "Heritage Markets". The Municipal bodies in collaboration with the tourism department shall promote such markets as tourist markets by incorporating such elements as may bring in local flavour in that market.

By the order of the Governor of Bihar,  
 CHAITANYA PRASAD,  
*Principal Secretary.*

**ANNEXURE**  
**ROAD DESIGING WITH STREET VENDING SPACE**

(in meters)

Sl. No.	Width of Road (in meters)	Footpath	Street Vending Space	Service Road	Cycle Track	Carriageway	Central verge	Carriageway	Cycle Track	Service Road	Street vending space	Footpath	Vending status	Conditionally allowed
1	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Not allowed	
		0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Allowed	No vehicular area
2	6.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Not allowed	
		0.0	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	Allowed	No vehicular area
3	9.0	1.0	0.0	0.0	0.0	3.5	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	1.0	Not allowed	
		1.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.5	3.5	0.0	0.0	0.0	1.0	Allowed	One way road
4	12.0	1.0	3.0	0.0	0.0	3.5	0.0	3.5	0.0	0.0	0.0	1.0	Allowed	One side
5	15.0	1.0	3.0	0.0	0.0	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0	1.0	Allowed	One side
6	18.0	1.0	3.0	0.0	0.0	6.0	1.0	6.0	0.0	0.0	0.0	1.0	Allowed	One side
7	24.0	1.5	3.0	0.0	0.0	8.5	1.0	8.5	0.0	0.0	0.0	1.5	Allowed	One side
8	30.0	1.5	3.0	0.0	1.0	9.0	1.0	9.0	1.0	0.0	3.0	1.5	Allowed	Both sides
9	36.0	2.0	3.0	0.0	1.5	11.0	1.0	11.0	1.5	0.0	3.0	2.0	Allowed	Both sides
10	40.0	2.0	3.0	0.0	1.5	13.0	1.0	13.0	1.5	0.0	3.0	2.0	Allowed	Both sides
11	60.0	3.0	4.0	5.0	2.0	15.0	2.0	15.0	2.0	5.0	4.0	3.0	Allowed	Both sides

Note: These calculations are subject to approval of traffic division for carrying capacity of vehicular traffic.

For two lane traffic minimum 7 meters is required for carrying traffic.

Minimum area available for street vending – 3 meters.

Minimum space requirement for pedestrian movements – 1.0 meters.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 119-571+200-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>